भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4638
दिनांक 21 अगस्त, 2025

तेल विपणन कंपनियों को घाटा

†4638. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को गैस के क्षेत्र में 43,000 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि का खुदरा कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): भारत, घरेलू एलपीजी खपत का लगभग 60% का आयात करता है। देश में एलपीजी का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़ा हुआ है। हालांकि, औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 51% की वृद्धि हुई (जुलाई 2023 में 385 यूएस डॉलर/मीट्रिक टन से जून, 2025 में 582 यूएस डॉलर/मीट्रिक टन), वहीं, घरेलू एलपीजी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य में 38% (अगस्त 2023 में 903 रुपए से जुलाई 2025 में 553 रुपए) की कमी की गई।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान, सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) 415 डॉलर प्रति एमटी से बढ़कर 712 डॉलर प्रति एमटी हुआ। हालांकि, बढ़े हुए अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का भार खुदरा मूल्यों पर पूरी तरह से नहीं डाला गया था, जिसकी वजह से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को भारी नुकसान हुआ। सरकार ने इस नुकसान की भरपाई करने के लिए ओएमसीज को वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ का एक बारगी मुआवजे का भुगतान किया।

वर्ष 2024-25 के दौरान एलपीजी के अंतरराष्ट्रीय मूल्य फिर से बढ़े और लगातार बढ़ रहे हैं। हालाँकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी के मूल्यों में हो रहे उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखने के लिए बढ़ी हुई लागत का भार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया था, जिससे तीन ओएमसीज को भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में किफायती मूल्यों पर घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है। सरकार ने हाल ही में ओएमसीज को हुए इस नुकसान की भरपाई हेतु, ओएमसीज को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी प्रदान की है।

सरकार और पीएसयू ओएमसीज द्वारा उठाए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरुप, पेट्रोल और डीजल के मूल्य नवंबर 2021 में 110.04 रुपये प्रति लीटर और 98.42 रुपये प्रति लीटर से घटकर क्रमश: 94.77 रुपये प्रति लीटर तथा 87.67 रुपये प्रति लीटर (1 अगस्त, 2025, दिल्ली के मूल्य) हो गए है।

केंद्र सरकार द्वारा दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की गई, जिसका फायदा पूरी तरह से उपभोक्ताओं को दिया गया था। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य वैट दरों में कमी की। दूसरी ओर, अप्रैल, 2025 में पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर उत्पाद शुल्क को 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया था परंतु इस बढ़ोत्तरी का भार उपभोक्ताओं पर डाला नहीं गया था।

*****